अध्याय 17

# सूचना प्रौद्योगिकी

## वार्षिक रिपोर्ट 2017–18

# सूचना प्रौद्योगिकी

आईसीटी लैंडस्केप के विविधीकरण तथा डिजीटल इंडिया पहल के साथ सरकार के लिए यह नितांत आवश्यक हो गया है कि उपभोक्ताओं की बदलती हुई अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन लाया जाए। वर्ष 2017–18 में कोयला मंत्रालय ने एनआईसी के साथ अथक प्रयास करते हुए आईटी कार्य परिस्थितियों एवं सेवा डिलीवरी में मानकीकरण एवं सुधार हेतु अग्रणी भूमिका निभाई है।

- कोयला मंत्रालय में एनआईसी कोल कम्प्यूटर सेंटर डिलिवरिंग तथा सुरक्षित मल्टी–प्लेटफार्म कम्प्यूटर आधारित अनुप्रयोगों तथा समाधानोंए डाटाबेस स्पोर्ट और इंटरनेटए ई–मेल नेटवर्क और विडियो कांफ्रेंसिंग सुविधाओं के लिए नवीनतम कंप्यूटर प्रणालियों से सुसज्जित है। कोयला मंत्रालय ने एनआईसी–मेघराज की क्लाउड सेवाओं को अपनाया है। इसका उद्देश्य अवसंरचना का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने तथा कोयला मंत्रालय के ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों के विकास और विस्तार को गति प्रदान करना है

- कोयला मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट http://coal.gov.in द्विभाषी, यूजर–फ्रेंडली है तथा इस पर सरल नैविगेशन से शीघ्र ही महत्वपूर्ण एवं नवीनतम अद्यतन सूचना प्राप्त की जा सकती है। क्लटर–फ्री रिस्पोंसिव डिजाइन से अन्त्य उपयोगकर्त्ताओं को साइट पर ही सभी हस्तचालित उपस्करों के बारे में सूचना प्राप्त करने में सहायता मिलती है। वरिष्ठ अधिकारियों का ब्यौरा, मंत्रालय का संगठनात्मक ढ़ांचा, अधीनस्थ कार्यालयों के लिंक्स, नीतियों, वार्षिक रिपोर्टों, प्रकाशनों, अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं, पॉलिसियों, आरटीआई के प्रकटीकरण, नवीनतम घोषणाओं तथा पत्रों आदि जैसी समृद्ध अद्यतित विषय वस्तु साइट पर उपलब्ध है।

  वेबसाइट जीआईजीडब्ल्यू अनुपालित तथा एसटीक्यूसी द्वारा प्रमाणित है।

इसके अलावाए मंत्री कार्यालय की वेबसाइट – http://ujwalbharat.gov.in की देखरेख तथा रख–रखाव मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह साइट माननीय मंत्री महोदय की देखरेख में रेल और कोयला मंत्रालय की पहलकदमियां तथा उपलब्धियां दर्शाती है।

- मंत्रालय में **कोल प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग पोर्टल** को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। यह व्यापक एमआईएस कोयला क्षेत्र–उद्योग के सभी स्टेकधारकों, कोयला कंपनियों, सीआईएल, एनएलसीआईएल राज्य सरकारों, मंत्रालयों/विभागों तथा कोयला मंत्रायल को जोड़ता है। विभिन्न राज्यों तथा/अथवा विभागों सहित लंबित मामलों वाली कोयला परियोजनाओं को इस प्रणाली में प्रस्तुत किया जाता है। इस मंच पर इन मुद्दों का गहन अनुवीक्षण, विचार–विमर्श और समाधान किया जाता है ताकि इस संबंध में संचयी सूचना प्रापण तथा निर्णय लेने में विलंब को दूर किया जा सके।

- कोयला मंत्रालय में **ई–फाईल** पूरी तरह कार्यात्मक है। अब मंत्रालय में कोई फिजिकल फाईल अथवा फिजिकल मूवमेंट नहीं है। हस्ताक्षर और सरकारी पत्र जारी करने के लिए डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) का प्रयोग किया जा रहा है। प्रभावी तथा पारदर्शी अंतर तथा अंतः सरकारी प्रक्रिया में शामिल होकर ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय में कोल **ई–ऑफिस मॉड्यूल्स–ई–लीव, ई–टूर, केएमएस** प्रचालनरत हैं। ई–फाईल और ई–ऑफिस में निरंतर कार्यचालन सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के लिए गैर–एनआईसीएनईटी नोड्स/लैपटाप पर वीपीएन की व्यवस्था की गई है।

- कोयला मंत्रालय ने अपने निवेशकों को **सिंग्ल विंडो** सुविधा प्रदान करनें के लिए एक वर्कफ्लो आधारित **ऑनलाईन कोयला अनापत्ति पोर्टल** विकसित किया है ताकि वे कोयला मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली **सभी मंजूरियों/अनापत्तियों तथा अनुमोदनों के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सके।** इस पोर्टल को तैयार कर दिया गया है। यह उन सभी स्टेकधारियों के लिए डैशबोर्ड के रूप में कार्य करेगा जो कोयला खान पट्टा, पूर्वेक्षण लाइसेंस, कोयला खान योजना, सीबीए अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण और खान खोलने की अनुमति के लिए अनापत्ति प्राप्त करने में शामिल हैं तथा इच्छुक हैं। कोयला मंत्रालय के कोयला अनापत्ति पोर्टल को मंत्रिमंडल सचिवालय के ई–निवेश पोर्टल के साथ भी जोड़ा गया है।

- एनआईसी ने **कोयला ब्लॉकों की मॉनीटरिंग** के लिए व्यापक एकीकृत एमआईएस विकसित करनें हेतु एक विस्तृत अध्ययन किया है। इस अध्ययन में वर्कफ्लो का विश्लेषण तथा कोयला ब्लॉकों हेतु स्टेकधारियों के बीच सूचना का आदान–प्रदान शामिल है। सभी आवश्यकताओं का आकलन किया गया है तथा क्रियात्मक आवश्यकता अध्ययन संबंधी शुरू किया गया है। सभी स्टेकधारियों की संतुष्टि के अनुसार चरणबद्ध ढंग से व्यापक सीबीसीएल प्रणाली को डिजाइन और विकसित करने के लिए कार्रवाई की गई है।
- कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा राज्यों को, राज्यों से राज्य द्वारा नामनिर्दिष्ट एजेंसियों (एसएनए) को और एसएनए से उपभोक्ताओं को पारदर्शी ढ़ंग से कोयला आबंटन को मॉनीटर करने के लिए **कोयला आबंटन मॉनीटरिंग प्रणाली (सीएएस)** विकसित की गई है। इस प्रणाली का अभिकल्पन एसएसएन के लधु तथा मध्यम क्षेत्र (पहले के नॉन–कॉर क्षेत्र) के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। इस वेब एप्लीकेशन का अभिकल्पन, विकास तथा रख–रखाव एनआईसी क्लाउड पर किया जा रहा है जिसमें सभी दूरस्थ स्टेकधारकों को आपस में जोड़ने तथा शीघ्र निर्णय लेने और पारदर्शिता स्थापित करने से संबंधित कई प्रमुख विशेषताएं हैं।
- मंत्रालय वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न कोल पीएसयू के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने एवं बोर्ड बैठकों के लिए मंत्रालय में स्थापित विडियों कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का व्यापक रूप से प्रयोग कर रहा है। लगभग 245.30 घंटे की संगोष्ठि अवधि सहित लगभग 86 वीसी सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं।
- मंत्रालय में दैनिक कार्यो के लिए निम्नलिखित कुछ मुख्य कार्यालयीन **ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर** का प्रयोग किया जा रहा है, जो इस प्रकार हैं :– **बायोमैट्रिक अटेन्डेंस सिस्टम, एसपीएआरआरओडब्ल्यू, ई–विजिटर, कोल अश्योरेंस मॉनीटरिंग सिस्टम, पे–रोल** हेतु कॉम्प्रेहेंसिव डीडीओ, वेतनपर्ची के लिए इंट्राकोल डैशबोर्ड, आयकर तथा जीपीएफ।
- मंत्रालय में **ई–गवर्नेंस एप्लीकिशेन** को कार्यान्वित किया गया है जो निम्नलिखित हैं : आरटीआई मामलों की देखरेख हेतु आरटीआईएमआईएस, एसीसी रिक्तियों की मॉनीटरिंग के लिए एवीएमएस, लोक शिकायत और संसदीय प्रश्नों तथा अनुपूरक एमआईएस के लिए सीपीजीआरएएमएस।